भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 257

जिसका उत्तर 03 फरवरी, 2023 को दिया जाना है ।

14 माघ, 1944 (शक)

नकली आधार कार्ड

257. श्री महाराजा संजाओबा लेशंबा :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर-पूर्व क्षेत्र में नकली आधार कार्ड उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक पता चले मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस चलन को रोकने के लिए क्या कार्रवाई करने पर विचार किया गया है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) से (ग): आधार प्रणाली एक सुदृढ़ और अत्यधिक सुरक्षित है और अपनी महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है।

आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 की धारा 3 के तहत आधार संख्या के रूप में भारत के प्रत्येक पात्र निवासी को डिजिटल पहचान जारी की जाती है। आधार अधिनियम, 2016 की धारा 4(3) निर्धारित करती है कि "प्रत्येक आधार संख्या धारक अपनी पहचान स्थापित करने के लिए, प्रमाणीकरण या ऑफ़लाइन सत्यापन के माध्यम द्वारा स्वेच्छा से भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपने आधार संख्या का उपयोग कर सकता है ..."।

डिजिटल पहचान/आधार को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के साथ ऑनलाइन/ऑफलाइन (आधार पत्र/ई-आधार/आधार पीवीसी कार्ड पर मुद्रित क्यूआर कोड को स्कैन करके) के माध्यम से प्रमाणित किया जाना है। यह सेवा यूआईडीएआई की वेबसाइट के साथ-साथ एमआधार ऐप पर भी उपलब्ध है।

इसके अलावा, जब भी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को नकली आधार के इस तरह के मामले की सूचना दी जाती है, तो वे आईपीसी और अन्य विधियों के प्रासंगिक वर्गों के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए भी बाध्य होते हैं।

****